DISCUSSION ON THE WORKING OF THE MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION *

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Statement by Minister, Shri S. Jaishankar.

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI S. JAISHANKAR): Sir, I rise to make a statement to this august House. ...*(Interruptions)*...

श्री उपसभापति : माननीय मंत्री जी के बयान की कॉपी कहां है? Let him continue.

SHRI S. JAISHANKAR: I will speak slowly. So, you will have enough time. ...*(Interruptions)*....

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please let him make his statement. ...*(Interruptions)*... Yes, it is being distributed. ...*(Interruptions)*...

SHRI S. JAISHANKAR: I rise to make a statement to this august House. ...*(Interruptions)*...

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा (हरियाणा): उपसभापति जी, यह जिम्मेदारी सेक्रेटेरिएट की है।

श्री जयराम रमेश (कर्नाटक): सर, यह रूल है कि सबके पास स्टेटमेंट होनी चाहिए।

श्री उपसभापति: स्टेटमेंट आ गई है। This is coming. ...*(Interruptions)*...

SHRI DEREK O'BRIEN (West Bengal): Sir, please adjourn the House for ten minutes. Let the copies of statement come first. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The statement has come. It is being distributed. ...*(Interruptions)*...

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, you adjourn the House for ten minutes. ...*(Interruptions)*... Let us be proper, please. ...*(Interruptions)*...

श्री जयराम रमेश: सर, यह रूल नहीं है।...**(व्यवधान)**... हमारे लिए अलग रूल है और इनके लिए अलग रूल है!...**(व्यवधान)**...

---

*Further discussion continued from the 14th March, 2022.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please be patient. The statement is coming. ...*(Interruptions)*... Just wait, please. ...*(Interruptions)*... Where is the Statement? ...*(Interruptions)*... Just wait, please. ...*(Interruptions)*...

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, please adjourn the House for ten minutes. ...*(Interruptions)*...

श्री जयराम रमेश: सर, यह रूल नहीं है।...**(व्यवधान)**... हमारे लिए अलग रूल है और इनके लिए अलग रूल है!...**(व्यवधान)**... हमारे लिए रूल है, लेकिन इनके लिए कोई रूल नहीं है!...**(व्यवधान)**... ऐसा कभी नहीं हुआ है।...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes, I will follow the rule. ...*(Interruptions)*... I will strictly follow the rule. ...*(Interruptions)*... Please, Derek*ji*. ...*(Interruptions)*...

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, my point of order is...*(Interruptions)*... As per the rules, we want the Minister's Statement on this important issue. ...*(Interruptions)*... It has not been circulated. I request you to adjourn the House for ten minutes. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We are moving to the next Business. ...*(Interruptions)*... We are moving to the next Business. ...*(Interruptions)*... Discussion on the working of the Ministry of Development of North-Eastern Region. Mr. Minister, please make your reply.

संस्कृति मंत्री; पर्यटन मंत्री; तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी): आदरणीय उपसभापति महोदय, कल इस सदन में North-East development और DoNER Ministry के बारे में चर्चा में लगभग 19 माननीय सदस्यों ने भाग लिया। इस चर्चा में डा. एम. थंबीदुरई जी, डा. सांतनु सेन जी, सुश्री सुष्मिता देव जी, डा. अमर पटनायक जी, श्री भुबनेश्वर कालिता जी, श्री कामाख्या प्रसाद तासा जी, श्री राकेश सिन्हा जी, श्री सर्वानंद सोनोवाल जी, श्री नबाम रेबिआ जी, श्री रिपुन बोरा जी, श्रीमती झरना दास बैद्य जी, श्री तिरुची शिवा जी, श्री अजीत कुमार भुयान जी, श्री प्रफुल्ल पटेल जी, श्री के.जी.केन्ये जी, प्रो. मनोज कुमार झा जी, श्री संजय राउत जी, श्री कनकमेदला रवींद्र कुमार जी और श्री वि. विजयसाई रेड्डी जी ने यहां पर नॉर्थ-ईस्ट के बारे में अपने-अपने विषय बताए। कुछ लोगों ने इसके बारे में सुझाव दिए हैं, कुछ लोगों ने समर्थन किया है और कुछ लोगों ने आलोचना भी की है। सर, प्रजातंत्र में अपने मन की बात रखना जरूरी भी है।

लेकिन कुछ माननीय सदस्यों ने valuable suggestions, guidance और directions भी DoNER Ministry के संबंध में चर्चा में दी हैं। मैं सबको धन्यवाद देता हूं। माननीय उपसभापति महोदय, हम सब जानते हैं पिछले आठ वर्षों में मोदी सरकार द्वारा नॉर्थ-ईस्ट रीजन में remarkable growth and development किया गया है। आदरणीय प्रधान मंत्री जी के 'Transforming India' के एजेंडा में पूर्वोत्तर क्षेत्र को top priority दी गई है। मैं दक्षिण से आता हूं, मगर मुझे पूर्वोत्तर की जिम्मेदारी दी गई है। आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी देश को जोड़ना चाहते हैं, इसीलिए दक्षिण के एक कार्यकर्ता को नॉर्थ-ईस्ट की जिम्मेदारी दी है। महोदय, भारत सरकार ने नॉर्थ-ईस्ट के बारे में holistic development strategy अपनाई है, जिसके अनुसार दो aspects पर continuous काम हो रहे हैं। वर्तमान के सभी challenges को दूर करना है, क्योंकि 2014 से पहले नॉर्थ-ईस्ट के विकास में अलग-अलग challenges थे। इन challenges को दूर करना नरेन्द्र मोदी जी की सरकार के सामने एक बहुत बड़ा मुद्दा था। हमने इसे दूर करने का प्रयास किया है। Inclusive growth और development के लिए new opportunities पैदा करने के लिए भारत सरकार ने प्रयास किया है। इसके परिणामस्वरूप अष्टलक्ष्मी राज्यों में न केवल अमेजिंग ग्रोथ होगी, बल्कि नॉर्थ इंडिया में पूरे भारत के लिए नई opportunities भी मिलेंगी।

आदरणीय उपसभापति जी, मुझे इस बात की खुशी है कि आज नॉर्थ-ईस्ट रीजन को डेवलेपमेंट, टूरिज़्म, कनेक्टिविटी, कल्चर, होप, aspiration और opportunities के लिए डेस्टिनेशन हब बनाने के रूप में जानते हैं। डेवलपमेंट के लिए most fundamental requirement पीस और स्टेबिलिटी होती है। आज जब हम नॉर्थ-ईस्ट को देखते हैं, तो हम बड़े स्केल पर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देखते हैं। हम इनवेस्टर के लिए नॉर्थ-ईस्ट में opportunities देने के लिए संपूर्ण प्रयास करते हैं। पूरे भारत के लोग नॉर्थ-ईस्ट संस्कृति और नए अवसरों के बारे में अधिक जानना चाहते हैं। नॉर्थ-ईस्ट के युवाओं में आज high aspirations के साथ, उनके डेवलपमेंट और उनको आगे बढ़ने के नए अवसर देने का भारत सरकार प्रयास कर रही है। इसका मुख्य कारण है कि नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में शांति और खुशहाली का नया दौर शुरू हुआ है जिसकी वजह से आज विकास के क्षेत्र को नई गति मिल रही है।

महोदय, मैं सदन के सामने कुछ डेटा प्रस्तुत करना चाहता हूं। 2014 के बाद insurgency-related incidents में बहुत कमी हुई है। 2014 में 824 incidents नॉर्थ-ईस्ट में हुए, जो कि 2020 में कम होकर 163 हो गए हैं। इसके साथ-साथ security forces killing भी 2014 से बहुत कम हुई है। 212 civilian deaths, जो 2014 में हुई थीं, वे आज 2020 में तीन तक घट गई हैं। Extremists surrendered - जो 2014 में 291 था, आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि 2020 में 2,696 extremists और insurgency groups ने भी surrender किया है। 445 arms surrender हुए हैं। ऐसे ही 2014 में 369 kidnappings हुई थीं, जो कि आज कम होकर 2020 में सिर्फ 69 kidnappings हुई हैं। ऐसे ही हमने कल लॉ एंड ऑर्डर के बारे में भी बात की है। Without peace, there is no development. Peace brings prosperity, peace brings development, इसीलिए peace के लिए, शांति के लिए भारत सरकार ने नॉर्थ-ईस्ट में बहुत प्रयास किए हैं। इसके बारे में मैं बाद में बोलूंगा। Memorandum of Settlement was signed on 10.08.2019.

Government of India ने Tripura National Liberation Front के साथ एग्रीमेंट किया है और उसके साथ शांति स्थापित की है। वैसे ही हमने बोडो ग्रुप्स के साथ भी चर्चा करके दिनांक 27.01.2022 को Memorandum of Settlement, MoS Agreement किया है। इसके साथ 1,615 ग्रुप्स ने सरेंडर किया है। वैसे ही हम Special Development Packages को उनके एग्रीमेंट के साथ implement कर रहे हैं। इसके साथ-साथ Bru families को financial assistance देने के लिए हमने Bru migrants के साथ चर्चा की है और उन्हें mainstream में लाने का प्रयास किया है। इसके साथ ही साथ भारत सरकार को शांति के लिए जितने भी प्रयास करने चाहिए, उतने प्रयास वह कर रही है। हम पहले देखते थे, जब मैं पार्टी के यूथ विंग में काम करता था, तो रोज़ पेपर में road blockade के बारे में पढ़ता था। वहां पर 10 दिन, 15 दिन के लिए स्कूल्स बंद, कॉलेज बंद हो जाते थे और मैं धरना, कर्फ्यू, फायरिंग इत्यादि के बारे में पढ़ता था। आज नॉर्थ-ईस्ट में न blockade है, न कर्फ्यू है, न स्कूल्स बंद हैं। आज पूरे नॉर्थ-ईस्ट में शांति है, जिसके कारण हम गर्व से कह सकते हैं कि आज सारी सरकारें - चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट्स हों, उनको आज विकास के बारे में सोचने का समय मिला है। वहां पर विकास करने की एक अहम भूमिका भारत सरकार निभा रही है। आज प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में शांति और खुशहाली का नया दौर शुरू हुआ है, जिसकी वजह से विकास को एक नई गति मिली है।

उपसभापति महोदय, मैं सदन के सामने insurgency groups के बारे में भी बताना चाहता हूं। वहां पर law and order अच्छा होने से विकास में तेज़ी लाने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट में बढ़ोतरी हुई है। माननीय नरेन्द्र मोदी जी के आने के बाद सेंट्रल मिनिस्ट्रीज़ के द्वारा 10 परसेंट GBS को और बढ़ावा दिया गया है। वर्ष 2001 में स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में इस मंत्रालय की शुरुआत की गई, इस मिनिस्ट्री की शुरुआत की गई। आज Central Ministries की, अगर 2014 से GSB को compare करते हैं, 10 per cent Gross Budgetary Support को compare करते हैं, तो हमने 2014 की तुलना में लगभग 110 per cent बढ़ोतरी की है।

उपसभापति जी, कल माननीय सदस्यों ने DoNER के Budget के बारे में जिक्र किया था, कुछ माननीय सदस्यों ने स्कीम्स के बारे में भी बात कही थी, पुरानी स्कीम्स जिनको 2017-18 में dismantle किया, उनके बारे में भी चर्चा की थी। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि हमने नई स्कीम्स चलाई हैं और नई स्कीम्स के द्वारा भी हमने अलग-अलग कार्यक्रमों की शुरुआत की है। माननीय सदस्यों ने 2020 के DoNER Budget के बारे में बात कही थी। मैं बताना चाहता हूं कि last year के Budget के मुकाबले में इस साल 2022-23 में 4,300 करोड़ रुपये दिए गए हैं, जिसमें से 2,800 करोड़ रुपये on-going schemes के लिए दिए गए हैं। इस साल पहली बार 1,500 करोड़ रुपये से new scheme PM-DevINE के नाम से प्रधान मंत्री जी ने सैंक्शन की है और फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट में इसकी घोषणा की है। वर्ष 2014-15 की तुलना में यह बढ़कर वर्ष 2022-23 में 18 per cent ज्यादा हो गया है। अगर इसको लास्ट ईयर के Budget से compare करते हैं, तो लास्ट ईयर बजट 2021-22 में यह 2,658 करोड़ रुपये था और अभी वर्तमान में 4,300 करोड़ रुपये हो गया है, आज यह 62 per cent अधिक हो गया है, जिसे इस साल हमारे प्रधान मंत्री जी ने और हमारे वित्त मंत्री जी ने नॉर्थ-ईस्ट के लिए दिया है। मैं बताना चाहता हूं कि केंद्र सरकार ने उन सभी डिपार्टमेंट्स के द्वारा नॉर्थ-ईस्ट के लिए 2014-15 के बाद 3 लाख करोड़

रुपये से ज्यादा धनराशि खर्च की है। महोदय, मैं यह 2014 के बाद का बता रहा हूं। अगर नॉर्थ-ईस्ट में देश की पॉप्युलेशन की तुलना की जाए, तो वह 3.78 परसेंट है। अगर भारत सरकार के ग्रॉस बजट से कम्पेयर करें तो नॉर्थ-ईस्ट में 10 परसेंट का फंड gross budgetary support के द्वारा देने का निर्णय लिया गया है।

माननीय उपसभापति महोदय, पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास की यात्रा में एक बड़ा चैलेंज कनेक्टिविटी का है। हमारी सरकार कनेक्टिविटी को प्राइयॉरिटी देते हुए इसके लिए बड़े प्रयास कर रही है। वह चाहे रेल कनेक्टिविटी हो, रोड कनेक्टिविटी हो, वॉटरवे कनेक्टिविटी हो, टेलीकॉम कनेक्टिविटी हो, वाई-फाई कनेक्टिविटी हो या एयर कनेक्टिवटी हो, इन सभी आठ राज्यों के साथ coordination and cooperation के साथ-साथ political connectivity भी की गई है। अलग-अलग पार्टी में होने के बाद भी हम मोदी जी के नेतृत्व में सभी पोलिटिकल पार्टीज़ के साथ, सभी स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ नॉर्थ-ईस्ट में पहली बार political connectivity भी लाए हैं। Last, but not the least, people to people, emotional connectivity प्रधान मंत्री जी के शब्दों में कहें तो आज नॉर्थ-ईस्ट में connectivity and integration को लेकर New North East vision, New India जैसा नया इतिहास बनाना हमारी सरकार का प्रयास है। सरकार नॉर्थ-ईस्ट को देश का Growth engine बनाने के मकसद से रेल कनेक्टिविटी पर तेजी से काम कर रही है।

माननीय उपसभापति महोदय, मैं इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि 2014 से लेकर 2020-21 के बीच में रेलवेज़ के लिए कुल एक्सपेंडिचर में 39,000 crore रुपये खर्च किए गए हैं। कितना खर्च किया है? 39,000 crore रुपये खर्च किए हैं। महोदय, यह ध्यान देने वाली बात है कि वर्तमान में नॉर्थ-ईस्ट रीजन की ज्योग्राफिकल डिफिकल्टी में भी 146 किलोमीटर की 121 टनल्स का निर्माण किया जा रहा है। वह एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। नॉर्थ-ईस्ट में रेलवेज़ के लिए 121 टनल्स का निर्माण हो रहा है। उनमें से 19 किलोमीटर की 25 टनल्स ऑपरेशनल हो चुकी हैं। इसके अलावा नॉर्थ-ईस्ट रीजन में सभी रेलवे लाइन्स के broad gauge conversion का वर्क पूरा हो गया है।

उपसभापति महोदय, नॉर्थ-ईस्ट के रेल प्रोजेक्ट्स के विकास में Capital connectivity का एक नया अध्याय जुड़ेगा। नॉर्थ-ईस्ट रीजन में difficult topography होने के कारण सेफ कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए highest scientific and engineering standards को इम्प्लिमेंट किया जा रहा है - उदाहरण के लिए मणिपुर की Jiribam-Imphal railway line एक engineering marvel है।

उपसभापति जी, इस बात को सभी माननीय सदस्यों को सुनना चाहिए कि यह हमारे लिए नहीं, बल्कि भारत के लिए, भारत के सभी इंजीनियर्स के लिए एक अभिनंदन का विषय है, गर्व का विषय है। इसमें नॉर्थ-ईस्ट में 141 metres height वाली रेल लाइन दुनिया के सबसे ऊँचे pier pillar पर बन रही है। अभी तक यूरोप में 139 मीटर pier pillar height की railway line थी, जिसकी ऊँचाई का वर्ल्ड रिकॉर्ड था, लेकिन आज नॉर्थ-ईस्ट रीजन में मणिपुर की 141 मीटर की pier pillar height की रेलवे लाइन बनाने के कारण भारत ने वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया है। त्रिपुरा के अगरतला में हाल ही में जन शताब्दी एक्सप्रैस inaugurate की गई। अगरतला रेलवे स्टेशन और मणिपुर में जिरिबाम रेलवे स्टेशन के बीच एक नई जन शताब्दी एक्सप्रैस प्रारंभ करने से direct

State connectivity के कारण यात्रा का समय भी आधा हो रहा है। इसमें असम का बदरपुर जंक्शन भी होगा।

उपसभापति महोदय, इसी वर्ष, जनवरी में मणिपुर की इकोनॉमी और कनेक्टिविटी को बूस्ट देते हुए पहली गुड्स ट्रेन भी शुरू की गई है। इसी के साथ इस वर्ष North-East Frontier Railway की पहली Parcel Cargo Express Train - Azara to Goa तक गई है। 2014 से पहले सिर्फ असम स्टेट कैपिटल गुवाहाटी से ही ट्रेन कनेक्टिविटी थी। 2014 के बाद ट्रेन कनेक्टिविटी अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल ईटानगर से जोड़ दी गई है, ट्रेन कनेक्टिविटी त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला से जोड़ दी गई है। मणिपुर की ट्रेन के द्वारा अभी कैपिटल कनेक्टिविटी नहीं है, मगर ट्रेन के द्वारा स्टेट में Jiribam से Vangaichungpao तक जोड़ दिया गया है। 2014 के बाद तीन स्टेट्स अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और मणिपुर में लोगों ने पहली बार ट्रेन देखी है। Remaining five States की कैपिटल्स की rail connectivity का काम चल रहा है। Total railway की line length 419 किलोमीटर्स है और 45,000 करोड़ रुपये से भारत सरकार इस rail connectivity पर काम कर रही है। नागालैंड-Dimapur-Zubza length 82 किलोमीटर्स है, कॉस्ट 6,647 करोड़ रुपये है और मार्च, 2026 तक लक्ष्य पूरा होगा। मिज़ोरम में Bhairabi-Sairang length 51 किलोमीटर्स है, कॉस्ट 6,527 करोड़ रुपये और इसका लक्ष्य मार्च, 2024 तक पूरा होगा। वैसे ही मणिपुर में जिरिबाम-इम्फाल की length 110 किलोमीटर्स है, कॉस्ट 14,322 करोड़ रुपये है और दिसम्बर, 2023 तक वह लक्ष्य पूरा होगा। सिक्किम में Sivok-Rangpo line की length 44 किलोमीटर्स है, कॉस्ट 8,153 करोड़ रुपये है और इसका लक्ष्य मार्च, 2023 तक होगा। मेघालय Tetelya-Burnihat की length 21 किलोमीटर्स है और कॉस्ट 1,043 करोड़ रुपये है। Burnihat-Shillong की length 108 किलोमीटर्स है और कॉस्ट 8,324 करोड़ रुपये है।

मैं यह बात क्यों बताना चाहता हूं, क्योंकि चाहे फ्लाइट्स हों, हेलिकॉप्टर्स हों या बसेज़ भी हों, नॉर्थ-ईस्ट के मौसम में वे 365 दिन काम नहीं आतीं। बहुत समय फ्लाइट्स कैंसिल होती हैं, हेलिकॉप्टर्स जा नहीं सकते हैं, बसेज़ का जाना भी मुश्किल होता है, इसलिए नॉर्थ-ईस्ट में अगर ठीक तरीके से विकास को जोर पकड़ना है, वहां टूरिस्ट्स को लाना है, इन्वैस्टर्स को लाना है, देश को देखने के लिए नॉर्थ-ईस्ट की जनता को बाहर जाना है और बाहर की जनता को नॉर्थ-ईस्ट जाना है तो ट्रेन्स जरूरी हैं। ट्रेन्स के बिना नॉर्थ-ईस्ट का विकास नहीं हो सकता है और यह नरेन्द्र मोदी जी की सरकार का लक्ष्य है।

2009-14 के बीच भारत सरकार ने एवरेज रेलवे के लिए 2,120 करोड़ रुपये प्रति वर्ष खर्च किए हैं। अभी 2020-21 में एवरेज 120% बढ़ी है और 2021-22 में 226% बजट बढ़ा है। मैं बताना चाहता हूं कि टूरिज़्म के दृष्टिकोण से, विकास के लिए और एम्प्लॉयमेंट जेनरेशन के लिए भी ट्रेन कनेक्टिविटी से आने वाले दिनों में नॉर्थ-ईस्ट बहुत अच्छे विकास के रास्ते पर जा सकता है। महोदय, कहीं भी विकास के लिए रोड्स और ट्रेन्स डेवलपमेंटल बैकबोन की तरह होती हैं। नॉर्थ-ईस्ट में रोड वर्क में सुधार के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास किये जा रहे हैं। 2014-15 में नॉर्थ-ईस्ट में नेशनल हाइवेज़ की length लगभग 10,905 किलोमीटर्स थी, आज वह बढ़कर 13,712 किलोमीटर्स हो गई है। नॉर्थ-ईस्ट में नेशनल हाईवेज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए आज नई रोड्स बन रही हैं। जैसे देश में इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, उसी संख्या में नॉर्थ-ईस्ट में भी नेशनल हाईवेज़ का कंस्ट्रक्शन करने के लिए भारत सरकार प्रयास कर रही है।

इसी के साथ-साथ मैं बताना चाहता हूं कि वहां के लिए डोनर मंत्रालय भी है। डोनर मंत्रालय के बारे में कल बात हुई है। डोनर मंत्रालय का लक्ष्य खुद का बजट रखना, खुद का डेवलपमेंट करना नहीं है। डोनर मंत्रालय सिर्फ कोऑर्डिनेशन करता है। डोनर मंत्रालय स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप है, वह कम्युनिकेशन और इन्फॉर्मेशन का गैप फिल-अप करता है। जब कनेक्टिविटी नहीं थी, तो नॉर्थ-ईस्ट से लोगों की यहां आकर मिनिस्टर से मिलना मुश्किल था, नॉर्थ-ईस्ट से यहां आकर प्रधान मंत्री जी से मिलना बहुत मुश्किल होता था, लोगों को आने में बहुत मुश्किल होती थी। इसी दृष्टिकोण से नॉर्थ-ईस्ट की देखभाल करनी चाहिए, नॉर्थ-ईस्ट के लिए अच्छा कम्युनिकेशन रखना चाहिए, नॉर्थ-ईस्ट के लिए कोऑर्डिनेशन रखना चाहिए, इसके लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस मंत्रालय का गठन किया था। इसलिए DoNER Ministry का बजट बहुत छोटा है, आप सब लोगों को मालूम है, फिर भी 2014-15 से नॉर्थ-ईस्ट में रोड्स के लिए 4,292 करोड़ सहित Ministry of Road Transport & Highways, Government of India ने टोटल 41,546 करोड़ खर्च किया है। विकास की गति को बढ़ावा देने के लिए 8 नॉर्थ-ईस्टर्न स्टेट्स में आज लगभग 75,000 करोड़ रूपया के works on-going हैं। यह आने वाले दिन में बहुत बड़ी मात्रा में नॉर्थ-ईस्ट का मुख-चित्र बदलेगा और नॉर्थ-ईस्ट के development का लक्ष्य बदलेगा। हमारे नितिन गडकरी जी; हमारी फाइनैंस मिनिस्टर, निर्मला सीतारमण जी और हमारे प्रधान मंत्री, नरेन्द्र मोदी जी का लक्ष्य है कि आने वाले 2-3 साल में नई-नई रोड्स की जो requirements हैं, उनके लिए हम DPR बना रहे हैं और नई-नई रोड्स बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। उनकी DPR के बाद लगभग 80,000 करोड़ की planning आने वाले 2-3 साल में होगी। 'भारतमाला परियोजना' के तहत projects में कुल 5,196 किलोमीटर length roads की planning की गई है, जिसमें 514 किलोमीटर का work पूरा हो गया है।

उपसभापति जी, इसी तरह से air connectivity है। माननीय सांसद महानुभावों ने air connectivity के बारे में बताया है। यह जरूरी है। देश की economic development की potential बढ़ाने के लिए air connectivity बहुत महत्वपूर्ण होती है। जो भी investment करना चाहते हैं, जिनको भी factory लगानी है, कोई industry लगानी है, कुछ IT projects लाने हैं, तो सभी लोग वहाँ air connectivity कैसी है, पहले वह देखते हैं। इसलिए air connectivity जरूरी है। इस दृष्टिकोण से पिछले कुछ वर्षों में air connectivity को बढ़ावा मिल रहा है। इसके कारण आज नॉर्थ-ईस्ट हर क्षेत्र में compete कर सके, यह भारत सरकार का लक्ष्य है। गवर्नमेंट नॉर्थ-ईस्ट एरिया में air connectivity बढ़ाने के लिए बड़े स्तर पर प्रयास कर रही है। Government of India ने air connectivity के विकास के लिए 900 करोड़ रुपया खर्च किया है। इसमें मौजूदा airports के upgradation, modernization तथा new airports और heliports के निर्माण के लिए आज भारत सरकार काम कर रही है। अगरतला का Maharaja Bir Bikram Airport, जिसको MBB Airport बोलते हैं, इसका उद्घाटन प्रधान मंत्री, मोदी जी के द्वारा किया गया है। इससे पहले केवल गुवाहाटी में international airport था। पहले नॉर्थ-ईस्ट में एक ही international airport था। अभी इम्फाल, मणिपुर में Bir Tikendrajit International Airport की शुरुआत 2017 में की गई। प्रधान मंत्री जी का उद्देश्य है कि हवाई चप्पल पहनने वाला आम आदमी भी हवाई जहाज में सफर कर सके। इस सपने को पूरा करने के लिए पूरे देश के आम नागरिकों के लिए regional

connectivity की स्कीम, 'उड़ान' है। उसके साथ पूर्वोत्तर को priority area के रूप में रखा गया है। नॉर्थ-ईस्ट में पर्यटन मार्गों सहित आज लगभग 46 मार्गों का संचालन किया जा रहा है। **...(व्यवधान)...** अरुणाचल प्रदेश में Pasighat-Holongi Greenfield Airport **...(व्यवधान)...**

श्री उपसभापति : प्लीज़, माननीय मंत्री जी का reply सुनिए।

श्री जी. किशन रेड्डी : इस Greenfield Airport के लिए 645 करोड़ की cost से development का काम चल रहा है। **...(व्यवधान)...** अगस्त, 2022 तक इसके पूरा होने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश में तेजू, असम में रुपसी, जोरहाट, लीलाबाड़ी, तेजपुर, वैसे ही मेघालय में बारापानी, नागालैंड में दीमापुर, सिक्किम में पाक्योंग नाम के airports और helipads को जोड़ने का प्रयास चल रहा है। Availability of land, commercial viability और traffic demand के आधार पर airports का upgradation/modernization, यह एक continuous process है। हमारी सरकार इस continuous process को जरूर आगे बढ़ाएगी। Agriculture और horticulture की क्षमता को बढ़ावा देने के लिए केन्द्रीय बजट में 2020-21 में शुरू की गई 'कृषि उड़ान' योजना को नॉर्थ-ईस्ट में भी शुरू किया गया है। 'कृषि उड़ान' के अंतर्गत नॉर्थ-ईस्ट में भी बागडोगरा, गुवाहाटी और अगरतला एयरपोर्ट से कृषि उत्पादन, जैसे pineapple, ginger, kiwi, organic turmeric produce के transportation का काम शुरू हो गया है। Digital India प्रधान मंत्री का एक नया vision है। 2014 के बाद digital connectivity दूरदराज़ के गांवों तक पहुंचनी चाहिए, यह हमारे प्रधान मंत्री जी की इच्छा है। पूर्वोत्तर में telecom connectivity और digital connectivity आदरणीय मोदी सरकार के लिए एक challenge थी। North East region में digital connectivity हर कोने तक ले जाने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास किए जा रहे हैं। पिछले सात वर्षों में North-East में digital connectivity बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने Rs. 3,466 crores खर्च किए हैं। Meghalaya and along the National Highways पर 2G+4G mobile connectivity available करवाने के लिए काम चल रहा है। Universal Service Obligation Fund (USOF) के तहत North-East Region में लगभग 5,600 villages को कवर करने के लिए 4,404 new towers लगाए गए हैं। उन towers के लिए Rs.3,715 crores खर्च करके North-East Region में mobile connectivity cover देने का प्रयास किया जा रहा है। North-East Region में 11,956 ग्राम पंचायतों को Bharat Net and Wi-Fi connectivity से जोड़ने का काम चल रहा है, जिसकी cost Rs.645 crores है। North-East Region में Waterways वहां के जीवन और संस्कृति का अभिन्न अंग हैं। प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में North-East में इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों को डेवलप करने के लिए सभी प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं।

DR. SANTANU SEN(West Bengal): Sir, I have a point of order.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Hon. Member has a point of order. Yes, Dr. Sen.

DR. SANTANU SEN: Sir, my point of order is related to Rule 240 - Irrelevance or repetition. It says, "The Chairman, after having called the attention of the Council to the conduct of a member who persists in irrelevance or in tedious repetition either of his own arguments."

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Santanu Sen ji, I am aware of it. I have seen it and I have already reminded all the hon. Members in this regard. Please sit down. Hon. Minister may please continue.

श्री जी. किशन रेड्डी : धन्यवाद उपसभापति जी, कल Act East Policy के बारे में भी मज़ाक उड़ाया जा रहा था, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपके काल में North-East Region बहुत neglect हुआ था, लेकिन हम अलग-अलग policies के द्वारा, different commitments के द्वारा North-East को encourage कर रहे हैं। आज वहां पर शांति है, वहां पर हम पैसा खर्च कर रहे हैं। किसी भी पॉलिसी का मज़ाक उड़ाना ठीक बात नहीं है। कल कुछ माननीय सदस्यों ने Act East Policy को criticize किया, मगर इस पॉलिसी के अंतर्गत पूर्वोत्तर में international connectivity पर ध्यान दिया जा रहा है। Agartala Akhaura Rail Link Project के अंतर्गत Agartala को Akhaura से Bangladesh Railway Network के माध्यम से जोड़ा जाएगा। इस railway network के द्वारा हमारे पड़ोसी देश के साथ traditional and historic connectivity भी मज़बूत होगी। एक बार यह railway network चालू होने के बाद कोलकाता और अगरतला के बीच passengers and goods transportation के लिए समय और यात्रा का खर्च दोनों कम होंगे। इसकी total length 12.26 kilometers है। इसमें Ministry of DoNER के द्वारा Indian side के 5.46 kilometers के लिए Rs. 580 crores खर्च किए जा रहे हैं। इसमें 6.8 kilometers length Bangladesh की side में आती है, वह पैसा भी भारत सरकार की Ministry of External Affairs के द्वारा खर्च किया जा रहा है। हमारे लिए यह rail link project बहुत महत्वपूर्ण है। Ministry of External Affairs के द्वारा Rs. 392 crores Bangladesh Railway Network पर खर्च किए जा रहे हैं। Indian side में railway track का सारा काम जून, 2022 तक पूरा करने का टार्गेट है। Bangladesh side में चलने वाला Railway Network भी हमारा ही है, लेकिन किसी कारण वह काम उतनी तेज़ी से नहीं हो पा रहा है, लेकिन 2022 के end तक उसको भी पूरा करने का टार्गेट है।

Kaladan Multi-modal Transit Transport Project and Trilateral Highway Project भी एक बहुत बड़ा historic step है। Myanmar के Sittwe Port के माध्यम से North-East को South-East Asia से sea के through और land connectivity के through Thailand से सीधा जोड़ेंगे। यहां ट्राइलेट्रल हाईवे का निर्माण किया गया है, जिससे लोग नॉर्थ-ईस्ट और साउथ-ईस्ट एशिया के बीच ड्राइव कर सकें। म्यांमार के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए Tamu-Moreh और Rih Zowkhawthar में दो इंटरनेशनल एंट्री-एग्जिट प्वाइंट ऑपरेशनल किये गये हैं।

महोदय, नॉर्थ-ईस्ट में एग्रीकल्चर एक प्रमुख विषय है, इसलिए भारत सरकार ने अभी कैबिनेट मीटिंग में ऑयल फर्म के बारे में एक नई स्कीम की घोषणा की है। उसमें 'नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल' के बारे में निर्णय लिया गया है, क्योंकि हर साल लगभग 80 हज़ार करोड़

रुपये से लेकर एक लाख करोड़ रुपये का एडिबल ऑयल हम इम्पोर्ट करते हैं, जबकि भारत सरकार चाहती है कि एडिबल ऑयल इम्पोर्ट न करना पड़े, बल्कि इसके लिए भारत में ही प्रावधान करके किसानों को एन्करेज करके, किसानों को इंसेन्टिव देकर इसका उत्पादन बढ़ाना चाहिए। इसी दृष्टिकोण से भारत सरकार की कैबिनेट ने 'नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल' के अंदर किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए 11,040 करोड़ टोटल आउटले का अप्रूवल किया है। मैं खुशी के साथ बताना चाहता हूं कि 11,040 करोड़ रुपये में सिर्फ 53 परसेंट, 5,850 करोड़ रुपये आज नॉर्थ-ईस्ट के लिए एलोकेट किये गये हैं। हम यह सबको बता सकते हैं कि भारत सरकार ने 50 परसेंट से ज्यादा एडिबल ऑयल नॉर्थ-ईस्ट के लिए एलोकेट किया है, ताकि नॉर्थ-ईस्ट में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो सके - यह श्री नरेन्द्र मोदी की सरकार के काम करने का तरीका है।

महोदय, असम में दीमा हसो डिस्ट्रिक्ट के मंदेरदिसा के 75 हेक्टेयर क्षेत्र में बम्बू के बारे में भी हम अलग-अलग काम कर रहे हैं। बम्बू सेक्टर को प्रोत्साहन देने के लिए नॉर्थ-ईस्ट रीजन, स्टेट गवर्नमेन्ट्स और केन्द्र सरकार के अलग-अलग डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं। वह ट्राइबल डिपार्टमेंट भी हो सकता है। इस तरह से अलग-अलग सरकारों के विभाग इसमें काम कर रहे हैं। नॉर्थ-ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड (NERAMAC) एक इंस्टिट्यूट है, यह बहुत पुराना इंस्टिट्यूट है, जो लॉस में था। अब इसे क्लोज़ करना है या नहीं करना है, आगे कैसे काम करना चाहिए, यह सोचकर इस इंस्टिट्यूट के रिवाइवल का निर्णय नरेन्द्र मोदी सरकार ने लिया है और इसका कैबिनेट ने अप्रूवल किया है। क्योंकि यह किसानों की क्रॉप की मार्केटिंग करने के लिए एक बड़ा साधन था, इसलिए लॉस होने के बाद भी भारत सरकार ने अलग पैकेज देकर इस संस्था को चलाने का प्रयास किया है।

इसी तरह से नौजवानों को रोजगार देने के लिए अलग-अलग कार्यक्रमों के द्वारा भारत सरकार प्रयास कर रही है। अभी बहुत कार्यक्रम चलाने हैं, ये कार्यक्रम ही काफी नहीं हैं, हम और कार्यक्रम भी चलायेंगे। रोजगार को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने जो भी करना है, वह नॉर्थ-ईस्ट में करेगी और यह काम राजनीति से ऊपर उठकर करना है। राज्य सरकारों के साथ मिलकर केन्द्र सरकार के अलग-अलग विभागों के द्वारा यह काम आगे बढ़ना चाहिए। उसमें NEDFI के द्वारा काम हो रहा है, SIDBI के द्वारा काम हो रहा है, स्टार्ट-अप इन्वेस्टमेंट का काम भी हो रहा है।

मैं सदन को बताना चाहता हूं कि 4 मार्च से 17 मार्च तक दुबई में वर्ल्ड एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है। नॉर्थ-ईस्ट में इन्वेस्टमेंट लाने के लिए 15 दिन का एक्सपो आठ गवर्नमेंट्स के साथ मिलकर आयोजित कर रहे हैं। इसके द्वारा हम दुनिया के अलग-अलग हिस्सों से नॉर्थ-ईस्ट में इन्वेस्टमेंट लाना चाहते हैं, यह हमारा प्रयास है।

महोदय, मुझे यह बताते हुए खुशी होती है कि नॉर्थ-ईस्ट के युवाओं ने देश का नाम रोशन किया है। हॉकी के बारे में कल भी चर्चा हुई थी, कल पटेल साहब ने बोला था कि हॉकी, फुटबाल, वेटलिफ्टिंग, बॉक्सिंग और पोलो आदि के क्षेत्र में नॉर्थ-ईस्ट का विशेष योगदान है। इसलिए खेल-कूद को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार ने मणिपुर में 922 करोड़ रुपये पहली नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को एलोकेट किये हैं। भारत सरकार ने देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मणिपुर में खोलने का निर्णय लिया है, क्योंकि उत्तर-पूर्व क्षेत्र में खेल प्रतिभा बहुत अधिक है। ओलिम्पिक्स में उत्तर-पूर्व के युवा खिलाड़ी अलग-अलग फील्ड्स में मेडल्स ला रहे हैं और आने वाले समय में और

भी मेडल्स लायेंगे। इसमें मेरिकॉम, मीराबाई चानू, लवलीन बोरगोहेन आदि खिलाड़ियों ने नॉर्थ-ईस्ट से आकर देश का नाम दुनिया में रोशन किया है। आदरणीय उपसभापति महोदय, नरेन्द्र मोदी जी की सरकार आने के बाद, ओलम्पिक में अगर हमारा कोई खिलाड़ी enter नहीं कर पाया, तो उसमें उसकी मदद की गयी। महोदय, एक खिलाड़ी थी, जिसकी हेल्थ ठीक नहीं थी, लेकिन वह अमेरिका जाना चाहती थी। वह खिलाड़ी भारत सरकार के खर्च से अमेरिका गयी, अमेरिका में उसके कोच द्वारा उसको कोचिंग दी गयी और आज वह ओलम्पिक में मेडल लायी है। इस प्रकार, भारत सरकार एक-एक खिलाड़ी को इतनी कमिटमेंट के साथ ट्रेनिंग देने का प्रयास कर रही है।

महोदय, आज के युग में किसी भी सेक्टर में बिना बिजली के डेवलपमेंट सम्भव नहीं है। आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी भारत में कुछ गाँव बिजली के बिना अपना जीवन गुजार रहे हैं। आज प्रधान मंत्री मोदी जी के नेतृत्व में घर-घर तक बिजली पहुँचायी गयी है। 'सौभाग्य योजना' के अन्तर्गत लगभग 3 करोड़ घरों को बिजली पहुँचायी जा रही है। इसके अलावा पावर कट की भी बात है। आज देश में कहीं भी रहें, पावर कट एक समस्या है। मैं आंध्र प्रदेश से आता हूँ। वहाँ industry owners ने इसलिए धरना दिया कि पावर कट नहीं होना चाहिए। जब कांग्रेस सरकार थी, तब 16 रुपये प्रति युनिट बिजली खरीदती थी। अब ओपन मार्केट में 3 रुपये प्रति युनिट बिजली मिल रही है। इसका कारण यह है कि नरेन्द्र मोदी जी की सरकार बिजली के बारे में एक अच्छा फैसला लेकर काम कर रही है।

महोदय, बिजली के बिना employment नहीं मिलता, बिजली के बिना industrialization नहीं होता है, बिजली के बिना न तो cell phone charge होता है, न telephone काम करता है और न ही घर में लाइट दिखती है, इसलिए हर व्यक्ति के घर में बिजली का होना जरूरी है। नॉर्थ-ईस्ट में difficult terrain होने के बावजूद भी isolated villages में भी, remotest corner में भी households में electricity पहुँचाने का प्रयास किया गया है। मैं कुछ examples भी देता हूँ। कुछ hills के ऊपर घर हैं। वहाँ ऊपर जाने के लिए, वहाँ electricity poles ले जाने के लिए Border Security Force के helicopters को use किया गया। हम हेलिकॉप्टर्स यूज़ करके भी वहाँ घरों तक electricity पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। वह काम अभी पूरा नहीं हुआ है, हम काम कर रहे हैं।

महोदय, पूर्वोत्तर पावर प्रोडक्शन के विकास पर फोकस के साथ-साथ positive industrial developmental ecosystem को encourage करने के प्रयास भी चल रहे हैं। 2014-15 के बाद भारत सरकार ने पावर प्रोजेक्ट्स के लिए नॉर्थ-ईस्ट के इन 8 प्रांतों में अभी तक 37,092 करोड़ रुपये खर्च किये हैं। अरुणाचल प्रदेश और असम में 2,000 megawatts का एक Subansiri Lower Hydroelectric Power Project है, जिसकी कॉस्ट 19,992 करोड़ रुपये है। यह देश के major projects में से एक है। नॉर्थ-ईस्ट रीजन का एक और दूसरा प्रोजेक्ट है, जो कि power system को improve करने का प्रोजेक्ट है, जिसकी कॉस्ट 6,700 करोड़ रुपये है। इस प्रोजेक्ट के द्वारा नॉर्थ-ईस्ट की स्टेट्स, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा में पावर सप्लाई में इम्प्रूवमेंट हो सकती है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में power transmission and distribution system को मजबूत करने की भी एक बड़ी योजना है, जिसकी कॉस्ट 9,129 करोड़ रुपये है। इसका काम चल रहा है। मैं DoNER के बारे में पहले ही बता चुका हूँ कि बजट कम रहता है, फिर भी, DoNER Ministry के अन्तर्गत भी 44 small power

projects हैं, जिनकी कॉस्ट 1,075 करोड़ है। इन projects के द्वारा industry sector को अवश्य बढ़ावा मिलेगा और नॉर्थ-ईस्ट में power supply streamline भी हो जायेगी।

महोदय, नॉर्थ-ईस्ट में पेट्रोलियम एक बड़ा source है। North-East Natural Gas Pipeline Grid Project एक ambitious ongoing project है, जिसकी estimated cost 9,265 करोड़ है। North-East Gas Grid (NEGG) project को 'Hydrocarbon Vision 2030' के अन्तर्गत propose किया गया। उसकी estimated cost 9,265 करोड़ है, जैसा मैंने अभी बताया। इन सभी 8 राज्यों में 1,656 किलोमीटर की length में pipeline grid डालना तय किया गया है और North-East Gas Grid के लिए 5,559 करोड़ रुपये के partial capital grant को मंजूरी दी गयी है। पूर्वोत्तर भारत में 1 लाख करोड़ की oil और गैस परियोजनाओं को 2025 तक पूरा करने का हमारे देश के सामने लक्ष्य है। इस लक्ष्य पर पहुंचने के लिए हम सभी को प्रयास करना चाहिए। पूर्वोत्तर investors के लिए attractive destination है। उसको ऐसा destination बनाने के लिए अनेक योजनाओं पर काम चल रहा है। Investors India के तहत एक North East Desk स्थापित किया गया है। वहां की स्टेट गवर्नमेंट के साथ काम करते हुए इन्वेस्टर्स के साथ MoU किया गया, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि North East की डोनर मिनिस्ट्री के साथ-साथ नार्थ-ईस्ट State Governments को इन्वेस्टर्स के साथ कैसा एमओयू करना चाहिए, उनका कैसे encouragement करना चाहिए, इसके बारे में भी सोच रहे हैं। उत्तर पूर्व राज्यों को भी हमने India Industrial Land Bank (IILB) में शामिल किया है। मोदी जी आज देश भर में 'One District One Product' को encourage कर रहे हैं। 'One District One Product' के साथ ही किसी एक जिले में वहां के एक important product को encourage करना चाहिए और उसके export के लिए प्रयास करना चाहिए। उस प्रोडक्ट में quality रहनी चाहिए, उसके प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहिए, उसकी marketing होनी चाहिए, यह मोदी सरकार का लक्ष्य है। इसके अंतर्गत export, trade और commerce जैसी एक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए 'One District One Product' में startups जैसे सेक्टर भी काम करें। Good governance का एक high standard स्थापित करते हुए सरकार के द्वारा इम्प्लिमेंट की जा रही योजनाओं का एक इम्पैक्ट स्थापित हो, इसके लिए हम प्रयास करें। लगातार पांच सालों तक नार्थ-ईस्टर्न स्टेट्स में हर कैबिनेट मिनिस्टर जाए, हर MoS जाए, इसके लिए पीएमओ और हमारे डोनर ऑफिस से monitoring होती है। पीएमओ को डोनर ऑफिस के द्वारा हर महीने रिपोर्ट देनी होती है। प्रधान मंत्री कार्यालय जरूर पूछता है कि इस महीने कितने मंत्री गए। हर स्टेट में हर 15 दिन में एक कैबिनेट मिनिस्टर जाना चाहिए, हर स्टेट में हर 15 दिन में एक MoS जाना चाहिए। उसी प्रकार से हर महीने 15 मंत्री नार्थ-ईस्ट में टूर करने का काम कर रहे हैं। उसमें State Government officials के साथ बातचीत होती है, North East Region beneficiaries के साथ बातचीत होती है और civil societies के साथ बातचीत होती है। हमारा प्रधान मंत्री कार्यालय इसकी मॉनिटरिंग करता है कि night halt कहां किया गया है। Night halt स्टेट कैपिटल में नहीं होना चाहिए, night halt जिले में होना चाहिए, उन्हें लोगों से मिलना चाहिए, यह टारगेट भी आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने सभी मंत्रियों को दिया है और यह काम डोनर मिनिस्ट्री के द्वारा implement किया जा रहा है।

SHRI JOHN BRITTAS (Kerala): Will you yield for one minute? ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Brittas, nothing is going on record. ...*(Interruptions)*... Mr. Brittas, you have no permission to speak. ...*(Interruptions)*..

श्री जी. किशन रेड्डी : उपसभापति जी, नार्थ-ईस्ट के विकास के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए UNDP के सहयोग से देश के लिए state SDG Index, और UT तैयार किया है। अभी तक देश के लिए SDG Index की तीन सीरीज़ जारी हो चुकी हैं। विकास कैसा होना चाहिए, कौन-कौन सी field में ज्यादा ध्यान देना है, उसके लिए ये index काम आते हैं। आज पहली बार नीति आयोग ने डोनर मिनिस्ट्री के द्वारा State SDG Index की Report के आधार पर district level SDG Index भी तैयार किया है। देश में अभी तक district level का index तैयार नहीं हुआ है, सिर्फ नार्थ-ईस्टर्न में हुआ है और यह आज सबसे पहले नार्थ-ईस्ट का आया है तथा 26 अगस्त, 2021 को नीति आयोग ने इसकी घोषणा की है। इस index का बहुत अधिक उपयोग नार्थ-ईस्ट रीजन में government policies को तैयार करने में हो रहा है। States and Central Government development programmes,welfare activities, projects, plannings पर इस index का उपयोग हो सकता है। 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास,सबका प्रयास' जो कि प्रधान मंत्री जी का लक्ष्य है, इस मूल भावना से पूर्वोत्तर क्षेत्र की 7-8 स्टेट्स के 28 डिस्ट्रिक्ट्स में हमने under developed blocks की पहचान की है। सेंट्रल सेक्टर की स्कीम्स के अलावा flagship programmes में सितंबर, 2020-21 तक 'जन-धन योजना' के तहत पूर्वोत्तर राज्यों में आज 434 lakh accounts खोले गये हैं। नॉर्थ-ईस्ट के दृष्टिकोण से 'आयुष्मान भारत योजना' बहुत उपयोगी है। वहाँ इस योजना के अंतर्गत 14 लाख परिवारों को आयुष्मान भारत कार्ड वितरित किया जा चुका है। वहाँ पर 'मनरेगा' के अंतर्गत 2016 से अब तक 31 हजार करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और 114 करोड़ man-days create किए गए हैं। 'जल जीवन मिशन' 2019 में launch किया गया और इसके अंतर्गत अभी तक 34 लाख घरों को सुविधा दी गई है। इसमें कुल coverage 50 percent है। उनको tap water connection दिए गए हैं। कुछ pipeline में हैं, वे sanction हो चुके हैं। इस मिशन का जो national average है, वह North East में बढ़ा है, यह खुशी की बात है।

महोदय, Covid relief और health के संदर्भ में भारत सरकार के द्वारा अलग-अलग काम किए जा रहे हैं। कल बात हो रही थी कि नॉर्थ-ईस्ट में कैंसर बहुत बड़ी समस्या है। हमारी सरकार इस बात को मानती है और इसके लिए अलग-अलग काम किए जा रहे हैं। कोविड के कारण पिछला वर्ष लगभग सभी क्षेत्रों के लिए challenging साबित हुआ था। केन्द्र सरकार ने कोविड के खिलाफ लड़ने के लिए, North East States का संवर्धन करने के लिए हर संभव प्रयास किया है। In the health sector, the Government has spent Rs.25,589 crores since 2014 onwards including Rs.548 crores by the Ministry of DoNER. The Ministry of DoNER has supported 66 special health projects for Rs.925 crores. भारत सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों में Covid-19 से लड़ने के लिए health facilities के लिए हर संभव प्रयास किया है। A.I.I.M.S. के लिए Rs.1,123 crores के expenditure का allocation किया है। Tata Cancer Research Institute से मिल कर 18 hospitals में काम चल रहा है।...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please, it is not permitted. ...*(Interruptions)*... Sushmita*ji*, please take your seat. ...*(Interruptions)*... Let him finish his speech. ...*(Interruptions)*... Only his speech is going on record. ...*(Interruptions)*... Please, Sushmita*ji*.

श्री जी. किशन रेड्डी : महोदय, अभी नॉर्थ-ईस्ट में health infrastructure के लिए अलग-अलग काम चल रहे हैं।**...(व्यवधान)...**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please. ...*(Interruptions)*... A statement is already there. ...*(Interruptions)*... सिर्फ माननीय मंत्री जी की बात रिकॉर्ड पर जा रही है।**...(व्यवधान)...**

श्री जी. किशन रेड्डी : महोदय, 2014 में budget estimation 36,107 करोड़ रुपए था, अभी इस साल budget estimation 76,040 करोड़ रुपए है। बजट को 36,000 करोड़ रुपए से 76,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाया गया है। यहाँ पर बताया जा रहा था कि वहाँ पर काम नहीं हुआ है। मैं बताना चाहता हूँ कि 2015-16 में बजट का 96.64 परसेंट खर्च हुआ था, वैसे ही 2017-18 में बजट का 97.3 परसेंट खर्च हुआ था और 2019-20 में बजट का 97.81 परसेंट खर्च हुआ था। सिर्फ एक Agriculture Department है, जिसमें कम खर्च हुआ है। मैं यह मानता हूँ कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लिए जितना पैसा allocate किया गया है, वह पूरा खर्च नहीं हुआ है। हम इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। DoNER Ministry का मंत्री बनने के बाद, आदरणीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के आदेश पर DoNER Ministry के officers Agriculture Ministry के officers के साथ meeting कर रहे हैं। वैसे ही Railway Ministry, Civil Aviation Ministry के साथ लगातार meetings करके, State Governments को confidence में लेकर, मुख्य मंत्रियों को confidence में लेकर, Chief Secretaries को confidence में लेकर स्टेट्स की जो समस्याएँ हैं, उनको हल करने के लिए भारत सरकार प्रयास कर रही है। कल कुछ अलग-अलग बातें भी बताई गईं। सर, मैं लॉ एंड ऑर्डर के बारे में बताना चाहता हूँ। वह किसकी देन है? हमसे पहले आप लोगों का राज था। स्टेट्स में काँग्रेस पार्टी की सरकार थी, सेंटर में काँग्रेस पार्टी की सरकार थी, मगर आप ही आपस में लड़कर वहाँ पर insurgency groups को बढ़ाते थे, आपस में लड़कर मुख्य मंत्री को निकालते थे। दस साल से सरकार ने नॉर्थ-ईस्ट की अलग-अलग स्टेट्स में एक स्टेबल गवर्नमेंट दी है। **...(व्यवधान)...**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please. ...*(Interruptions)*... Please. ...*(Interruptions)*... सिर्फ माननीय मंत्री जी का जवाब ही रिकॉर्ड में जा रहा है। **...(व्यवधान)...**

श्री जी. किशन रेड्डी : मैं भारत सरकार के द्वारा नॉर्थ-ईस्ट की सारी जनता को यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हमारी सरकार नॉर्थ-ईस्ट के विकास के लिए प्रतिबद्ध है, नॉर्थ-ईस्ट के विकास के लिए काम करना चाहती है। **...(व्यवधान)...**

श्री जॉन ब्रिटास : *

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please. ...*(Interruptions)*... Please, Shri John Brittas. ...*(Interruptions)*...

श्री जी. किशन रेड्डी : नॉर्थ-ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए काम करना चाहती है। **...(व्यवधान)...**

श्री उपसभापति : केवल माननीय मंत्री जी की बातें ही रिकॉर्ड पर जा रही है। **...(व्यवधान)...** Please. ...*(Interruptions)*...

श्री जी. किशन रेड्डी : सर, प्रधान मंत्री कार्यालय में every month नॉर्थ-ईस्ट के 30 मेजर प्रोजेक्ट्स प्राइम मिनिस्टर डायरेक्ट रिव्यू करते हैं। **...(व्यवधान)...**

श्री उपसभापति : कृपया आपस में बात न करें। **...(व्यवधान)...**

श्री जी. किशन रेड्डी : Every month 30 प्रोजेक्ट्स सेलेक्ट करके प्रधान मंत्री जी नॉर्थ-ईस्ट के बारे में रिव्यू करते हैं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please. ...*(Interruptions)*... Please, take your seats. ...*(Interruptions)*...

श्री जी. किशन रेड्डी : हम नॉर्थ-ईस्ट के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। **...(व्यवधान)...**

श्री उपसभापति : सिर्फ माननीय मंत्री जी की बात ही रिकॉर्ड पर जा रही है। Please, Shri John Brittas. ...*(Interruptions)*...

सुश्री सुष्मिता देव : *

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please. ...*(Interruptions)*... Please, Sushmita*ji*. ...*(Interruptions)*...

श्री जी. किशन रेड्डी : उपसभापति जी, मैं नॉर्थ-ईस्ट की सारी जनता को बताना चाहता हूँ कि last seven-and-a-half years के बाद आज वहाँ शांति है, उस शांति को कायम रखें, peace कायम रखें। **...(व्यवधान)...**नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में सारे भारत की जनता नॉर्थ-ईस्ट के विकास के लिए committed है। **...(व्यवधान)...** हम इसे आने वाले दिनों में बताएंगे। **...(व्यवधान)...** हमारे

---

* Not Recorded.

प्रधान मंत्री जी बार-बार बोलते हैं कि तब तक भारत का विकास नहीं हो सकता है, जब तक भारत के साथ-साथ नॉर्थ-ईस्ट का विकास न हो, इसलिए हम भारत के साथ-साथ नॉर्थ-ईस्ट भारत के हर क्षेत्र में भी विकास करना चाहते हैं। यह हमारी commitment है, हम इस commitment के साथ आगे बढ़ेंगे। इसके लिए मैं सभी सदस्यों से अनुरोध करना चाहता हूँ। सर, सभी सरकारों में कमी रहती है, लेकिन कमी रहने के बाद हमारा लक्ष्य क्या है, हमारी commitment क्या है, हम पहले यह बताना चाहते हैं। हमारी commitment है, इसलिए मैं सभी सदस्यों से अनुरोध करता हूँ कि इस विकास में सरकार के साथ जुड़िए, सरकार के साथ हाथ से हाथ मिलाकर आगे बढ़िए, जय हिन्द!

STATEMENTS BY MINISTERS- *Contd.*

Situation in Ukraine

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, the Statement by Minister, Shri S. Jaishankar. Please.

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI S. JAISHANKAR): Sir, I rise to make a statement to this august House on the situation in Ukraine and the implications that it has had for India, including for our nationals resident there. Despite the challenges posed by a serious ongoing conflict, we have ensured that about 22,500 citizens have returned home safely. The House would recognize the complexity of the various endeavours that have made it possible. Allow me to share them in some detail.

As hon. Members may be aware, a tense situation between Russia and Ukraine erupted into conflict on 24th February, 2022. The root causes for this are complex, going back to a range of issues including the security architecture, political governance and inter-state politics. To that was added the challenges of implementing understandings reached earlier. What is pertinent to note is that the hostilities placed the Indian community of 20000-plus in direct danger. Even while we were participating in the global deliberations of this evolving situation in the UN Security Council, the pressing challenge was to safeguard our citizens and ensure that they were not in harm's way.

At the direction of the Prime Minister, we launched Operation Ganga, thereby undertaking one of the most challenging evacuation exercises during an ongoing conflict situation. Hon. Members should know that our community was dispersed across Ukraine, posing its own logistical challenges. The exercise was undertaken at